शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक-16 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 11-18 अप्रैल 2022 मूल्य पांच रूपए

क्या मुफ्ती योजनाओं की घोषणा केजरीवाल के डर का परिणाम है?

- अनुराग की आप में सफल सेंधमारी भी मुख्यमंत्री के मनोबल को कायम नहीं रख पायी
- क्या इन योजनाओं को नड्डा का समर्थन हासिल है?
- क्या प्रदेश की जनता सत्ता में वापसी के इन प्रयासों की कीमत करीब 500 करोड़ का और कर्ज झेल कर चुका पायेगी

शिमला/शैल। क्या जयराम सरकार आम आदमी पार्टी के हिमाचल का विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान से मनोवैज्ञानिक दबाव में आ गयी है? यह सवाल इसलिये उठना शुरू हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के मौके पर प्रदेश की जनता को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति मुफ्त और सरकारी बसों में महिलाओं को बस किराये में 50% की छूट देने की घोषणा की है। इन घोषणाओं पर इसी वर्ष 1 अगस्त से अमल शुरू हो जायेगा। इससे पहले 60यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया गया था। जो पहली अप्रैल से लागू होना था। अब मुफ्त बिजली की मात्रा दोगुनी से भी बढ़ा दी गयी है। स्मरणीय है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के दो दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों की प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक हुई थी। इस बैठक में दो अधिकारियों ने इन मुफ्ती योजनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुये यह आशंका व्यक्त की थी कि यदि ऐसी घाषणाओं को सख्ती से समय रहते न रोका गया तो कुछ राज्यों की स्थिति जल्द ही श्रीलंका जैसी हो जायेगी। इस बैठक की चर्चा बहुत वायरल हुई है। इस परिदृश्य में जयराम ठाकुर की इन घोषणाओं को आम आदमी पार्टी के आसन भय के साथ जोडकर ही देखा जायेगा।

फिर यह सब कुछ केजरीवाल के मण्डी रोड शो के बाद हुआ है। इसी रोड शो की सफलता के बाद आप ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अपने विधानसभा क्षेत्र सराज में भी ऐसा ही रोड शो करने का ऐलान किया हुआ है। बल्कि इस प्रस्तावित रोड शो से पहले अब कांगड़ा में रोड शो करने की तारीख की घोषणा कर दी है। कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और प्रदेश की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। यही नहीं आप को प्रदेश में पांव पसारने से रोकने के लिये जो सफल सेंधमारी की थी और नड्डा ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर विराम लगाते हुये प्रधानमंत्री से जो ईमानदारी का प्रमाण पत्र जारी करवा कर उत्साहवर्धन का जो प्रयास किया था उस सबका सच भी इन घोषणाओं से पूरी तरह अर्थहीन होकर रह गया है। आम आदमी पार्टी ने सराज की ओर से जो रूख करने का फैसला लिया है उसके पीछे वहां हुये विकास के सारे दावों और आरोपों का सच सराज से लेकर पूरे प्रदेश के सामने रखने की योजना है। चर्चाओं के मुताबिक सराज में देखने वाले विकास के नाम पर मुख्यमंत्री के अपने आवास होटल सराज और चुनाव क्षेत्र में बने करीब एक दर्जन हेलीपैड को छोड़कर और कुछ गिनती योग्य बड़ा नहीं है। होटल सराज बनने के साथ ही प्राइवेट सैक्टर को दे दिया गया है। क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने के लिए मल्टी टास्क वर्कर भर्ती में 50% का जो कोटा मुख्यमंत्री के लिये रखा गया था उस 50 को प्रदेश उच्च न्यायालय के दखल ने शून्य करके रख दिया है। ऐसे में आगे इन्हीं मुफ्ती योजनाओं का सहारा है। लेकिन जिस तरह से यह योजनाएं भी केजरीवाल के डर से का परिणाम कहीं जाने लगी हैं। उससे इन योजनाओं पर होने वाले खर्च की भरपाई सरकार कहां से करेगी यह और सवाल उठना शुरू हो गया है।

वैसे तो यह घोषणाएं पहली अगस्त से लागू किये जाने की बात कही गयी है। लेकिन यह संभावना भी बराबर बनी हुई है कि कहीं हिमाचल और गुजरात के चुनाव उत्तराखंड के उपचुनाव के साथ ही न करवा लिए जायें। यह उपचुनाव 15 सितम्बर तक हो जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा होता है तो बहुत संभव है कि यह मुफ्ती की घोषणाएं चुनाव आचार संहिता के साये में लागू ही न हो पायें। अन्यथा इन्हें तुरंत प्रभाव से भी लागू किया जा सकता था। क्योंकि कर्ज लेकर घी पीने की परम्परा को ही तो आगे बढ़ाना है। इस परिदृश्य में आप की धार को कुन्द करने के जितने भी प्रयास किये जायेंगे वह निरर्थक ही प्रमाणित होंगे। क्योंकि इन मुफ्ती घोषणाओं को चुनावों की पूर्व संध्या पर किसी भी तर्क और गणित से जायज नहीं ठहराया जा सकेगा। जब 60 यूनिट बिजली मुफ्त देने की पहली घोषणा की गयी थी तब इसके बदले में 92 करोड़ बिजली बोर्ड को देने की बात की गयी थी। अब इसकी मात्रा दोगुनी करने से बोर्ड को दी जाने वाली रकम बढ़कर 200 करोड़ हो जायेगी। इसी के साथ जब ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुफ्त उपलब्ध करवाने और महिलाओं को बस किराये में 50% छूट का बिल भी साथ जुड़ जायेगा तो एक झटके में ही कम से कम 500 करोड़ का कर्ज बढ़ाने का प्रबन्ध सत्ता में वापसी के भरोसे को कायम रखने के लिये राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व ने कर लिया है। इस मुफ्ती योजना को मुख्यमंत्री के वकीलों नड्डा और अनुराग का कितना समर्थन हासिल है इसके लिये उनके ब्यान का इंतजार है। बाकी फैसला प्रदेश की जनता और बेरोजगार युवाओं के बढ़ते आंकड़े को करना है। क्योंकि यह सब सीधे उनके भविष्य के साथ जुड़ा है।

क्या 'जय और तय' के नारों से ही कांग्रेस भाजपा से सत्ता छीन लेगी?

शिमला/शैल। विधानसभा के चुनाव तय समय से पहले हो जाने की संभावनाएं बराबर बनी हुई है। हिमाचल में जो मुकाबला पहले कांग्रेस और भाजपा में ही होना तय माना जा रहा था उसमें अब आम आदमी पार्टी की एंट्री ने सारे राजनीतिक गणित और समीकरणों में उलटफेर खड़ा कर दिया है। क्योंकि आप में कांग्रेस और भाजपा से ही नाराज कार्यकर्ता एवं नेता शामिल हो रहे हैं। फिर जयराम ने आप के दिल्ली मॉडल की नकल करके भले ही अपने और पार्टी के लिये राष्ट्रीय स्तर पर सिर दर्द खड़ा कर लिया हो लेकिन कांग्रेस को वह अपने मुकाबले में ही नहीं मानते हैं यह संदेश देने में तो सफल हो ही गये हैं। इस परिदृश्य में कांग्रेस की चुनौतियां दोगुनी हो जाती हैं। उसे केजरीवाल के मॉडल को भी तथ्यों के साथ ध्वस्त करना होगा और जयराम तथा उनके सलाहकारों के बौद्धिक दिवालीयेपन को भी उजागर करना होगा। यह करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को अपनी कुण्ठाओं से बाहर निकालना होगा। पूरे अध्ययन के साथ आप और जयराम के खिलाफ प्रमाणिक साक्ष्य प्रदेश की जनता के सामने रखने होंगे। लेकिन जो कांग्रेस घोषणा के बाद भी सरकार के खिलाफ अभी तक आरोप पत्र नहीं ला पायी है क्या वह आने वाले दिनों में सफलता के साथ इस जिम्मेदारी को अंजाम दे पायेगी? यह सवाल इसीलिये उठने लगा है क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में अपनी ही जय और अपने ही तय होने के नारे लगवाने में व्यस्त हो गये हैं। डॉ. अंबेडकर जयंती के अवसर पर हमीरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में 'जय सुक्खू तय सुक्खू' 'जय कांग्रेस तय कांग्रेस' के नारे लगने से यह चर्चा आम आदमी तक पहुंच गयी है। इस आयोजन में हमीरपुर में कांग्रेस के तीनों विधायक सुक्खू, लखनपाल और राजेंद्र राणा हाजिर रहे हैं। इन नारों से यही संदेश जाता है कि यदि कांग्रेस को चुनाव में बहुमत मिलता है तो सुक्खू ही मुख्यमंत्री होंगे। यह

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने डॉ.भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर ने पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए जीवन पर्यन्त कार्य किया और सामाजिक भेदभाव और जाति व्यवस्था के विरूद्ध आवाज उठाई।

राज्यपाल सोलन में डॉ. भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर सामाजिक दलित पीड़ित उत्थान संस्थान सोलन द्वारा आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भारत के संविधान के निर्माता होने के साथ-साथ डॉ. अंबेडकर ने लोगों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के दृष्टिगत निर्बाध रूप से कार्य किया और गरीबों, शोषितों और पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया।

उन्होंने कहा कि देश में संतों की समृद्ध परंपरा रही है। डॉ. अंबेडकर के कार्य, विचार और योगदान को देखकर लोग उन्हें संत भी कहते हैं। डॉ. अंबेडकर का जन्म ऐसी ही संत परंपरा में हुआ था। उन्होंने समाज के एक विशेष वर्ग के लिए ही नहीं, अपितु पूरे देश के उत्थान के लिए कार्य किया। हमें उनके आदर्शों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर के जीवन में घटित कई घटनाओं से उनके जीवन में रही कई समस्याओं का पता चलता है। उन्होंने कहा कि इन सब विपत्तियों के बावजूद बाबा साहेब ने सबसे ज्यादा उपाधियां हासिल की थीं। उन्होंने कहा कि वह केवल पिछड़े वर्ग के नेता नहीं थे, वास्तव में वह राष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और महिला शिक्षा में बहुमूल्य योगदान दिया।

राज्यपाल ने कहा कि उनका पूरा जीवन समाज और देश के लिए समर्पित था और यह सभी की जिम्मेदारी है कि हम सभी जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर उनकी जयंती मनाएं। उन्होंने कहा कि वह सही मायने में एक हिंदू धार्मिक सुधारक थे और अंत तक हिंदू धर्म से जुड़े रहे। वह हिन्दू समाज की कुरीतियों से भलीभांति परिचित थे। उन्होंने अपने और अपने साथियों के मध्य राष्ट्रवाद की भावना को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि आज डॉ. अंबेडकर के विचारों और शिक्षाओं को समझने और सभी को उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है।।

इस अवसर पर राज्यपाल ने समाज के लिए में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि सामाजिक दलित पीड़ित उत्थान संस्थान पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब समाज में असमानता बढ़ी तो पिछड़े वर्ग में भी कई महान शख्सियतों का जन्म हुआ। संत कबीर, संत रविदास जैसे कई संतों ने समाज को दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद डॉ. अंबेडकर ने समानता का संदेश दिया।

उन्होंने कहा कि मध्यकाल में संतों ने जो संदेश दिया था, उसे आजादी के बाद डॉ. अंबेडकर ने आगे बढ़ाया। उन्होंने एक अलग समाज बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पिछड़े वर्ग के युवाओं का आहवान किया कि वे डॉ. अंबेडकर के विचारों पर अडिग रहें, बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा लें। उन्होंने कहा कि इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा।

प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि डॉ. अंबेडकर एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। उनकी शिक्षा और प्रतिष्ठा में योगदान देने वाले शिक्षक और अन्य लोग सद्भावना के उदाहरण हैं। उन्होंने संविधान को सर्वोपरि बनाया। उन्होंने लोगों से संविधान में निहित अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि आज समाज से भेदभाव समाप्त हो रहा है और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि सभी मिलकर देश को विकास के पथ पर आगे ले जा सकें।

इस अवसर पर पूर्व सांसद एवं हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेन्द्र कश्यप ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए अनुसूचित जाति आयोग के गठन पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने समाज को समानता और भाईचारे का रास्ता दिखवाया और शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि पिछड़े वर्ग के छात्रों को बैंकों से सुगमता से ऋण मिल सके। उन्होंने कहा कि आयोग समाज में सौहार्द और समरसता बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। खादी बोर्ड के अध्यक्ष पुरूषोतम गुलेरिया, नगर निगम सोलन की महापौर पूनम ग्रोवर, प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद, पूर्व मंत्री महेन्द्र नाथ सोफत, प्रदेश भाजपा कार्यकारी सदस्य राजेश कश्यप, उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी, पुलिस अधीक्षक वीरन्द्र शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने बिलासपुर में युद्ध स्मारक का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों की याद में हर जिले में युद्ध स्मारक बनाए जाने चाहिए ताकि भावी पीढ़ी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके और हम उनके प्रति आभार भी व्यक्त कर सकें। राज्यपाल बिलासपुर में युद्ध शहीद स्मारक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता ने शहादत को सम्मानित किया है और यह उनका सौभाग्य है कि उनके माध्यम से यह कार्य सम्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे वीर जवान सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और हर समय समर्पण भाव के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिस कारण इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन संभव हो पाता है। उन्होंने जवानों के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों की स्मृति में स्मारक समर्पित करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अभियान से जुड़े सदस्यों ने इस विचार को मूर्तरूप दिया है और वे सभी प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि समाज के लिए समर्पित और काम करने वाले लोगों से सीख लेने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने इस अवसर पर शहीद परिवारों को सम्मानित किया। उन्होंने एक ईट शहीद के नाम अभियान टीम के सदस्यों को भी सम्मानित किया।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए किस्मत कुमार ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि आज का दिन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने नरसंहार किया था और राष्ट्र की खातिर 1000 से अधिक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज का दिन उन क्रांतिकारियों को याद करने का है। उन्होंने कहा कि एक ईट शहीद के नाम अभियान हमारी भावनाओं से जुड़ा है और शहीदों को समर्पित है।

एक ईट शहीद के नाम अभियान के संयोजक संजीव राणा ने राज्यपाल का स्वागत किया और युद्ध स्मारक के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

एक ईट शहीद के नाम अभियान के प्रांत संयोजक सूबेदार मेजर प्रेम सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इससे पहले, राज्यपाल ने भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया और युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने यहां स्थापित 147 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकारः ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

राज्यपाल ने ऊना में चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के चार वर्ष पूर्ण होने पर प्रयास संस्था के सौजन्य से आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने नाहन, पांवटा साहिब, जसवां परागपुर और देहरा विधानसभा क्षेत्रों के लिए चार नई मोबाइल स्वास्थ्य वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मोबाइल कैंसर डिटैक्शन बस के 600वें कैम्प का भी शुभारंभ किया। चिकित्सा शिविर में उत्तर भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों से आए डाक्टरों ने लोगों की जांच की।

राज्यपाल ने प्रयास संस्था की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था ने चार वर्षों में अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि संस्था के आरम्भ में तीन मोबाइल यूनिट संचालित की जा रही थी और आज सात जिलों के 23 विधानसभा क्षेत्रों में 32 मोबाइल यूनिट संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से लोगों को घर-द्वार पर मेडिकल टेस्ट की सुविधा के साथ निःशुल्क दवाईयां और उपचार की सुविधा उपलब्ध हो रही हैं।

राज्यपाल ने 14 मोबाइल स्वास्थ्य सेवा यूनिट के सदस्यों सहित मेडिकल कैम्प में सेवाएं प्रदान कर रहे चिकित्सकों को सम्मानित किया।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के साथ-साथ प्रयास संस्था के माध्यम से प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परोपकारी गतिविधियों की सराहना की। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर तथा छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिन्दल, चिंतपूर्णी के विधायक बलवीर चौधरी, उपायुक्त ऊना राघव शर्मा, पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ठाकुर, राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार, राज्य व्यापार प्रमुख कमल चुग्ग, निदेशक यूपीएल लिमिटेड विक्रम श्रॉफ, प्रयास संस्था के महासचिव विजय कुमार तथा समन्वयक संजीव राजपूत उपस्थित थे।

राज्यपाल ने की लॉरेंस स्कूल सनावर के स्मरणोत्सव समारोह की अध्यक्षता

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सोलन जिले के लॉरेंस स्कूल सनावर की उत्कृष्टता के 175वें वर्ष के स्मरणोत्सव समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि लॉरेंस स्कूल ने अपनी स्थापना के बाद से एक लंबी यात्रा पूरी की है।

राज्यपाल ने कहा कि यह संस्थान अपनी स्थापना के 175 वर्ष ऐसे समय में मना रहा है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि आज हम संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 132 जयंती भी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शिक्षण संस्थान ने देश और दुनिया को उच्च स्तर के विद्यार्थी दिए हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर हर क्षेत्र में स्कूल का नाम रौशन किया है। उन्होंने कहा कि जो संस्कार, अनुशासन और आदर्श स्कूल से मिले वे यहां के विद्यार्थियों ने समाज को दिए हैं।

आर्लेकर ने कहा कि विद्यार्थी लगातार अपने शिक्षक के संपर्क में रहता है इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वे उसमें नैतिक मूल्यों के साथ-साथ राष्ट्रीयता की भावना का संचार भी करें। उसके समग्र विकास में स्कूल के वातावरण का अधिक प्रभाव पढ़ता है। राज्यपाल ने स्कूल प्रबंधन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुसरण करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल की अपनी परम्पराएं रही हैं लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहां के विद्यार्थियों के जीवन में और गुणात्मक योगदान देने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने इस विषय पर स्कूल में सम्मेलनों के आयोजन पर बल दिया।

राज्यपाल ने इस अवसर पर स्कूल पत्रिकाएं और स्मारक पदक भी जारी किया।

स्कूल के मुख्याध्यापक श्री हिम्मत सिंह ढिल्लों ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा स्कूल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उपलब्धियों की जानकारी दी।

स्कूल समिति के अध्यक्ष मेजर संजीव शर्मा, संचालन समिति के अध्यक्ष जनरल कुलप्रीत सिंह, सोलन की उपायुक्त कृतिका कुल्हारी, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र शर्मा, बोर्ड के सदस्य और अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

बिलासपुर में एम्स और विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा

शिमला/शैल। राज्य सभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के कोठीपुरा स्थित परिसर में

विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

इस अवसर पर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि मरीज की जान बचाने के लिए अपनी जान लगा देना ही एम्स की संस्कृति है। इसलिए, संस्थान की गुणवत्ता और संकाय की क्षमता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से ही बिलासपुर में 750 बिस्तर क्षमता का एम्स संस्थान आकार ले रहा है, जिस पर लगभग 1471 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। इसका अधिकांश कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके विभिन्न भवनों के निर्माण के साथ-साथ चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जनता को अतिशीघ्र स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण लाभ मिल सके।

जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि कीरतपुर-नेर चौक फोरलेन नेशनल हाईवे का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि लगभग 47 किलोमीटर 750 मीटर लंबे इस मार्ग पर 22 बड़े पुलों, 15 छोटे पुलों और पांच डबल लेन सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। फोरलेन का कार्य पूर्ण होने पर गरामोड़ा से मंडी की दूरी 40 किलोमीटर कम होगी तथा यात्रा का समय भी लगभग सवा घंटा कम हो जाएगा। बिलासपुर और गरामोड़ा की दूरी भी 23 किलोमीटर तक कम हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि 6753 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली भानुपल्ली रेलवे लाईन का कार्य भी प्रगति पर है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में 48.6 किलोमीटर लाईन बिछाई जाएगी। इस ट्रैक पर 20 सुरंगें और 26 मुख्य पुल बनाए जाएंगे। इस परियोजना के तहत बैरी तक भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि गोविंद सागर झील में समा चुके बिलासपुर के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों को पुनर्स्थापित करने के लिए 1400 करोड़ की परियोजना तैयार की गई है, जिसे तीन चरणों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। प्रदेश सरकार ने बजट में इसकी भी घोषणा की है। इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से पूरा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि परियोजना के पहले चरण में इन मंदिरों को नाले का नौण में पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसी परियोजना के दूसरे चरण में सांडू के मैदान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तीसरे चरण में मंडी भराड़ी के पास बैराज बनाकर मंदिरों के आस-पास एक जलाशय बनाया जाएगा। इसमें रिवर फ्रंट और वॉकवेज इत्यादि विकसित किए जाएंगे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से जहां बिलासपुर एक आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, वहीं इससे बिलासपुर का पुराना इतिहास और संस्कृति भी पुनर्जीवित होगी, जिससे सभी बिलासपुरवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स और हाईड्रो इंजीनियरिंग महाविद्यालय को प्रतिदिन 21 लाख लीटर पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 66 करोड़ रुपये की कोलडैम उठाऊ पेयजल परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसका 97 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। बिलासपुर में 50 बिस्तर क्षमता के मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र के निर्माण पर 10 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है और इसका 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर की मरम्मत पर लगभग अढ़ाई करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं, जिसका कार्य प्रगति पर है।

इस अवसर पर एम्स परियोजना, भानुपल्ली रेल परियोजना, फोरलेन नेशनल हाईवे और गोविंदसागर में जलमग्न मंदिरों की पुनर्स्थापना से संबंधित प्रस्तुति भी दी गई।

मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 13.08 करोड़ रुपये के लोकार्पण किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह तारा देवी के 4.28 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित भवन तथा राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शोघी के 8.80 करोड़ रुपये की लागत से

निर्मित भवन का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर शोघी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आनंदपुर-शोघी-जलेल-थड़ी-बढ़ई उठाऊ सिंचाई योजना और खटनोलू नाला से समस्त कोट पंचायत के लिए उठाऊ सिंचाई योजना का प्रावधान करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शोघी में टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और संस्कृत अध्यापकों के पद सृजित करने, विद्यालय की चार दिवारी के लिए 50 लाख रुपये तथा साउंड सिस्टम के लिए 3 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

उन्होंने शोघी में एचपीएसईबी का उपमंडल खोलने की घोषणा भी की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अध्यापकों से विद्यार्थियों को केंद्रित दृष्टिकोण के साथ गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने और उनका मार्गदर्शन करने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा दूरदराज क्षेत्रों में वर्तमान आवश्यकता के आधार पर आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है। प्रदेश के छात्रों में योग्यता की कमी नहीं है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन के साथ सही अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। भाजपा सरकार ने हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। सवा चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान कोविड-19 के संकट के बावजूद सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में देश कोविड के संकट काल से बाहर निकल कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा भी दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे महिलाओं को लगभग 60 करोड़ रुपये के लाभ प्राप्त होंगे। सरकार द्वारा प्रथम जुलाई से सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक जीरो बिल की सुविधा प्रदान करने व उनसे कोई विद्युत बिल न लेने का निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के 11.5 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को 250 करोड़ रुपये के लाभ प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे सभी परिवारों से पानी का कोई बिल न लेने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को 30 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान होंगे।

इस अवसर पर जय राम ठाकुर ने मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत स्थापित इकाई का निरीक्षण भी किया।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोविड-19 के दौरान सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के फलस्वरुप प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के कार्यान्वन से सरकारी विद्यालयों में शिक्षा और गुणात्मकता सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित किया है। प्रदेश सरकार विश्वास और विकास के साथ प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया।

विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

कैलाश फेडरेशन व भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों का विवरण देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है।

भाजपा नेता डॉ. प्रमोद शर्मा ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर प्रधान ग्राम पंचायत कोट नेहा मेहता ने स्वयं सहायता समूह की ओर से चीड़ की पत्तियों से बना उत्पाद भेंट किया।

विद्यालय की प्रधानाचार्य अमिता गुप्ता ने मुख्यमंत्री और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। मंडल अध्यक्ष दिनेश ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, उपायुक्त आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉ. मोनिका और गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अंबेडकर चौक, शिमला में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान के निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर ने समरसता, सौहार्द और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए योगदान दिया। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों और गरीबों के कल्याण एवं उनके अधिकारों के लिए जीवन-भर कार्य किया। हमें उनके जीवन मूल्यों और आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर सूचना एवं जन संपर्क विभाग के कलाकारों ने भक्ति संगीत प्रस्तुत किया।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, महापौर नगर निगम शिमला सत्या कौंडल, हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, उप-महापौर शैलेंद्र चौहान, नगर निगम के पार्षद, पूर्व महापौर व पार्षद, पूर्व विधायक और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी और पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका इस अवसर पर उपस्थित थीं।

मीडिया के विभिन्न माध्यमों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अधिकारियों एवं मीडिया समन्वयकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए सूचना के

प्रभावी सम्प्रेषण के लिए नवीनतम तकनीक और मीडिया के विभिन्न माध्यमों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों एवं मीडिया समन्वयकों को प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों तथा विकासात्मक उपलब्धियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए तत्परता से कार्य करने को कहा।

उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। विभाग को योजनाओं की सफलता और लाभार्थियों के सम्बन्ध में तथ्यों को दक्षता से प्रचारित करना चाहिए। उन्होंने विकासात्मक समाचारों के प्रचार-प्रसार तथा मीडिया से बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए और प्रतिबद्धता से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से प्रदेशवासियों के जीवन में आये सकारात्मक बदलाव और विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में एक प्रभावी योजना बनाकर उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

जब तक आप खुद पर विश्वास नही करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नही कर सकते।

.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

चुनाव प्रक्रिया पर अब बहस जरूरी है

इस समय देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें यह सवाल हर रोज बड़ा होता जा रहा है की आंखिर ऐसा हो क्यों रहा है? यह सब कब तक चलता रहेगा? इससे बाहर निकलने का पहला कदम क्या हो सकता है? पिछले अंक में महंगाई के साथ उठते सवालों पर चर्चा उठाते हुये पाठकों से यह वायदा किया था कि अगले अंक में इस पर चर्चा करूंगा। अभी संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत का हरिद्वार से एक बयान आया है कि अगले पन्द्रह वर्षों में अखंड भारत का सपना पूरा हो जायेगा। एक तरह से इसके लिये समय सीमा तय कर दी गयी है। भाजपा संघ की राजनीतिक इकाई है यह सब जानते हैं। इस नाते संघ प्रमुख का यह बयान भाजपा सरकार के लिये अगले पन्द्रह वर्षों का एजेंडा तय कर देता है। यह भी सभी जानते हैं कि अखंड भारत की परिकल्पना में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मयनमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सभी शामिल हैं। इस परिकल्पना और संघ प्रमुख के इस एजेंडे का अर्थ क्या हो सकता है यह समझना मैं पाठकों पर छोड़ता हूं। इसमें उल्लेखनीय यह भी है कि डॉ. भागवत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसमें जो भी व्यवधान पैदा करने का प्रयास करेगा वह नष्ट हो जायेगा। इस प्राथमिकता में देश की आर्थिकी, महंगाई और बेरोजगारी के लिये क्या स्थान है यह समझना भी अभी पाठकों पर छोड़ता हूं। क्योंकि सभी के भविष्य का प्रश्न है।

देश का एजेंडा संसद के माध्यम से सरकार तय करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद का चयन लोगों के वोट से होता है। इसके लिए हर पांच वर्ष बाद पंचायत से लेकर संसद तक सभी चुनाव की प्रक्रिया से गुजरते हैं। सांसदों से लेकर पंचायत प्रतिनिधियों तक सब को मानदेय दिया जा रहा है। हर सरकार के कार्यकाल में इस मानदेय में बढ़ौतरी हो रही है। लेकिन क्या जिस अनुपात में यह बढ़ौतरी होती है उसी अनुपात में आम आदमी के संसाधन भी बढ़ते हैं शायद नहीं। इन लोक सेवकों का यह मानदेय हर बार इसलिये बढ़ाया जाता है कि जिस चुनावी प्रक्रिया को पार करके यह लोग लोकसेवा तक पहुंचते हैं वह लगातार महंगी होती जा रही है क्योंकि राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों पर किये जाने वाले खर्च की कोई सीमा ही तय नहीं है। आज जब चुनावी चंदे के लिये चुनावी बाण्डस का प्रावधान कर दिया गया है तब से सारी चुनावी प्रक्रिया कुछ लखपतियों के हाथ का खिलौना बन कर रह गयी है। इसी कारण से आज हर राजनीतिक दल से चुनावी टिकट पाने के लिये करोड़पति होना और साथ में कुछ अपराधिक मामलों का तगमा होना आवश्यक हो गया है। इसलिये तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन अभी तक भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा भी जुमला बनकर रह गया है कि संसद और विधानसभाओं को अपराधियों से मुक्त करवाउंगा।

पिछले लंबे अरसे से हर चुनाव में ईवीएम को लेकर सवाल उठते आ रहे हैं। इन सवालों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को शुन्य बनाकर रख दिया है। ईवीएम को लेकर इस समय भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लंबित है। फिर विश्व भर में अधिकांश में ईवीएम की जगह मत पत्रों के माध्यम से चुनाव की व्यवस्था कर दी गयी है। इसलिए आज देश की जनता को सरकार, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों पर यह दबाव बनाना चाहिये कि चुनाव मतपत्रों से करवाने पर सहमति बनाएं। इससे चुनाव की विश्वसनीयता बहाल करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ चुनाव को धन से मुक्त करने के लिये प्रचार के वर्तमान माध्यम को खत्म करके ग्राम सभाओं के माध्यम से मतदाताओं तक जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। सरकारों को अंतिम छः माह में कोई भी राजनीतिक और आर्थिक फैसले लेने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इस काल में सरकार को अपनी कारगुजारीयों पर एक श्वेत पत्र जारी करके उसे ग्राम सभाओं के माध्यम से बहस में लाना चाहिये। ग्राम सभाओं का आयोजन राजनीतिक दलों की जगह प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिये।

जहां सरकार के कामकाज पर श्वेत पत्र पर बहस हो। उसी तर्ज पर अगले चुनाव के लिये हर दल से उसका एजेंडा लेकर उस पर इन्हीं ग्राम सभाओं में चर्चाएं करवायी जानी चाहिये। हर दल और चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिये यह अनिवार्य होना चाहिये कि वह देश-प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर एजेंडे में वक्तव्य जारी करें। उसमें यह बताये कि वह अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए देश-प्रदेश पर न तो कर्ज का भार और न ही नये करों का बोझ डालेगा। मतदाता को चयन तो राजनीतिक दल या व्यक्ति की विचारधारा का करना है। विचारधारा को हर मतदाता तक पहुंचाने का इससे सरल और सहज साधन नहीं हो सकता। इस सुझाव पर बेबाक गंभीरता से विचार करने और इसे ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक बढ़ाने-पहुंचाने का आग्रह रहेगा। यह एक प्रयास है ताकि आने वाली पीढ़ियां यह आरोप न लगायें कि हमने सोचने का जोखिम नही उठाया था।

एक भारत श्रेष्ठ भारत:लोक संगीत का महत्व

माई नी मेरिये ... शिमले दी राहे चंबा कितनी कू दूर..

नवीन श्रीजीत यू आर

जब केरल की 14 वर्षीय देविका एस. एस. ने इस हिमाचली लोक गीत को गाया और अक्तूबर 2020 में अपने स्कूल शिक्षक के पास भेजा, तो उन्हें नहीं पता था कि यह सोशल मीडिया पर वायरल हो जायेगा। यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के संज्ञान में आया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर टिप्पणी की 'देविका पर गर्व' है और उनकी सुंदर प्रस्तुति 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के सार को मजबूत करती है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ट्विटर पर लिखा, 'केरल की बेटी देविका ने अपनी मधुर आवाज में प्रसिद्ध हिमाचली गीत 'चंबा कितनी की दूर' गाकर हिमाचल का गौरव बढ़ाया है।

देविका ने अपने स्कूल में एक भारत श्रेष्ठ भारत गतिविधियों के हिस्से के रूप में हिमाचली गीत गाया था। गोरतलब है कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्तूबर, 2015 को प्रधान मंत्री द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जोड़ी की अवधारणा के माध्यम से आपसी समझ और बातचीत को बढ़ावा देना है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में, सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा गया है। यह परिकल्पना की गई है कि उनके युग्मित राज्यों के साथ पारस्परिक जुड़ाव राज्यों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। इस आदान-प्रदान के माध्यम से, विभिन्न संस्कृतियों वाले विभिन्न राज्यों के लोगों की भाषा, संस्कृति, व्यंजनों, परंपराओं और सर्वोत्तम प्रथाओं के ज्ञान से राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाया जायेगा। यह आगे सहयोग और नई संभावनाओं के मार्ग प्रशस्त करेगा।

उदाहरण के लिये, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, हिमाचल प्रदेश को केरल के साथ जोड़ा गया है, इसलिए केरल में हिमाचली व्यंजनों, साहित्य, संगीत, कला को बढ़ावा दिया जाएगा और इसी तरह पंजाब को आंध्र प्रदेश के साथ, चंडीगढ़ को दादरा और नगर हवेली के साथ, जम्मू-कश्मीर को तमिलनाडु के साथ जोड़ा गया है। प्रत्येक माह अलग-अलग युग्मित राज्यों को उनके कार्यक्रमों के संचालन के लिए आवंटित किया जाता है तथा इसी के मद्देनजर यह अप्रैल युग्मित राज्यों हिमाचल प्रदेश और केरल को आवंटित किया गया है।

देविका द्वारा गाया गया लोक गीत सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच संबंध बना सकता है जो भूगोल से अलग हैं लेकिन भारत द्वारा एकजुट हैं।

लोक गीतों में आम लोगों की सबसे बुनियादी मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने की अनूठी क्षमता होती है फिर चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो या केरल, लोक गीत प्रेम, भगवान की स्तुति, प्रकृति की सुंदरता, नायकों की प्रशंसा और सामाजिक मनोरंजन के बारे में गाते हैं। लोक गीत का एक विशिष्ट पहलू यह है कि यह कई पीढ़ियों से आम लोगों द्वारा लिखे जाते रहे है। यह पिछली पीढ़ियों के समान है जो वर्तमान पीढ़ियों से बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, उन्होंने क्या किया और उनकी विश्वदृष्टि क्या थी।

केरल में लोक संगीत को 'नादनपट्टू' के नाम से जाना जाता है। केरल में इसकी एक समृद्ध परंपरा है। उदाहरण के लिए, 'वंचिपट्टू' या 'नाव गीत' की लय नाव की रोइंग के समान है। लय में वृद्धि से नाविकों को तेजी से पंक्तिबद्ध करने में मदद मिलती है । यह अभी भी केरल के सांप नौका दौड़ में लोकप्रिय है।

'मप्पिलापट्टू' उत्तरी केरल में मुस्लिम समुदाय को दर्शाने वाले लोकगीत हैं। वे केरल की लोक संगीत परंपरा और अरबी संगीत परंपरा का मिश्रण हैं।

'वडक्कन पट्टुकल' (उत्तर के गीत) मध्ययुगीन काल के मलयालम गाथागीतों का एक संग्रह है जो नायकों की कहानियों के बारे में गाता है। इन गीतों ने केरल की अपनी मार्शल आर्ट 'कलारी पयट्टू' द्वारा लोगों के जीवन पर प्रभाव को भी दिखाया है।

'ओनापट्टुकल' ओणम के त्योहार से संबंधित लोक गीतों को संदर्भित करता है। यह भगवान महाबली की वार्षिक यात्रा, कृषि, समृद्धि और बेहतर समय की आशा के बारे में है।

भारत भर में लोक संगीत प्रेम और भाईचारे के सार्वभौमिक मूल्यों को सिखाता है और हमारी पिछली पीढ़ियों के जीवन का दस्तावेजीकरण करता है। इसलिए लोक संगीत का संरक्षण और लोक संगीतकारों का समर्थन और भी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने लोक कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों की रक्षा, प्रचार और संरक्षण के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर लोक गीतों और लोक नृत्यों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इनका मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में है।

मन की बात के फरवरी के कार्यक्रम में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से भारत में विभिन्न प्रकार के गीतों को बढ़ावा देने के लिए कहा था, ताकि ऐसा माहौल बनाया जा सके जिसमें हम 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' का अनुभव कर सकें। उन्होंने युवाओं से आजादी का अमृत महोत्सव को नए तरीके से मनाने के लिए भारतीय भाषाओं के लोकप्रिय गीतों के वीडियो बनाने का आग्रह किया। यदि हिमाचल प्रदेश के लोग इस एक भारत श्रेष्ठ भारत युग्मित महीने में केरल और इसके विपरीत लोक गीतों को बढ़ावा देते हैं, तो यह दोनों राज्यों के बीच उनकी लोक संगीत परंपरा में और अधिक आपसी समझ तथा सांस्कृतिक संपर्क पैदा करेगा।

एक भारत श्रेष्ठ भारत महीना केरल और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक-दूसरे के बारे में अधिक जानने और एक-दूसरे की संस्कृति, भाषा, परंपराओं को बढ़ावा देने का एक शानदार अवसर है।

आयुष्मान भारत ने बदली स्वास्थ्य देखभाल सेवा की तस्वीर

डॉ.आर.एस.शर्मा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

भारत के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य देखभाल को विश्व-स्तरीय बनाने के ध्येय से2017 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) को अंगीकार किया था। इसे अंगीकार करते समय सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह उभरकर आया था कि किस तरह भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को तीव्रता से प्राप्त करे। भूत में भारत में स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति पर अंतर्दृष्टि डालने पर यह साफ-साफ दिख रहा था कि स्वास्थ्य देखभाल की लागत पर होने वाले खर्चो के कारण आम आदमी की क्रय शक्ति प्रभावित हो रही है, अत: इन खर्चो को कम करना भी एनएचपी के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था। उपरोक्त कारणों की पृष्ठभूमि में ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय) की परिकल्पना की गई ताकि स्वास्थ्य सेवा वितरण को समग्र दृष्टिकोण के साथ तीव्रता प्रदान की जा सके और देश के अंतिम जन की पहुंच किफायती एवं गुणवत्ता-युक्त स्वास्थ्य सेवाओं तक सुलभता से हो सके।

ऐसा नहीं है कि आयुष्मान भारत पीएम-जय स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में देश का पहला प्रयास था बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), राज्यों की योजनाओं जैसे आंध्र प्रदेश में आरोग्य श्री, महाराष्ट्र में जीवनदायी योजना जैसी पूर्ववर्ती योजनाओं को भी भरपुर श्रेय दिया जाना चाहिए। वर्तमान में यह भी सच है कि एबी पीएम-जय ने स्वास्थ्य बीमा/ आश्वासन के क्षेत्र में बाकी तमाम हितधारकों को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल किया है।

इसके विस्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मौजूदा समय मेंआयुष्मान भारत पीएम-जय राज्य स्वास्थ्य योजनाओं के साथ मिलकर 14 करोड़ से अधिक परिवारों (70 करोड़ व्यक्तियों) के लाभार्थी आधार को कवर कर रहा है। अभी तक इस योजना के तहत लगभग 18 करोड़ व्यक्तियों की पहचान कर उनका आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। वैश्विक महामारी के बीच महज 3.6 वर्षो के अपने छोटे से क्रियान्वयन काल में एबी पीएम-जयने अस्पताल-भर्ती के साथ लगभग 3. 28 करोड़ उपचार प्रदान किया है, जिस पर उपचार खर्च 37,600 करोड़ से ज्यादा का रहा है।

वर्तमान में जिस प्रकार से आयुष्मान भारत पीएम-जय अपनी उड़ान भर रहा है, यह माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण और कैबिनेट द्वारा संकल्पित बहुमुखी नीतिगत ढांचे का परिणाम है। आयुष्मान भारत पीएम-जय के पीछे के मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्पष्ट करने वाले प्रमुख बिन्दुओं को निम्न रूपों में समझा जा सकता है।

व्यापक स्वास्थ्य लाभ पैकेज

एबी पीएम-जय की जब प्रारंभ हुआ था तब 1,393 उपचार पैकेज था लेकिन अब इसका विस्तार 1670 उपचार पैकेजों तक किया जा चुका है। इन पैकेजों में ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोवस्कुलर सर्जरी आदि जैसी विभिन्न चिकित्सा विशेषताओं के उपचार के लिए 5 लाख रुपये तक प्रति लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष कवर प्रदान किया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने और बाद के खर्चो का भी ख्याल इन पैकेजों में रखा गया है, इतना ही नहीं पोर्टिबिलीटी फीचर के माध्यम से देश के दूर-दराज के लाभार्थी भी देश के किसी भी कोने में जाकर आयुष्मान सूचीबद्ध अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल ले सकते हैं।

स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अभिसरण और एकीकरण

एबी पीएम-जय के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को उनके क्रियान्वयन के तरीके, लाभार्थी डेटाबेस को चुनने और अस्पतालों का नेटवर्क बनाने में काफी लचीलापन प्रदान किया गया था। इसके अलावा, एनएचए ने मौजूदा राज्य आधारित योजनाओं के साथ भीतत्परता-पूर्वक अभिसरण किया। वर्तमान में, एबीपीएम-जय को 25 से अधिक राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाओं के साथ मिलकर लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, देश भर के 600 से अधिक जिलों में जिला क्रियान्वयन इकाइयां (डीआईयू) स्थापित की गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एबीपीएम-जय की प्रशासनिक पहुँच लाभार्थी के घर तक हो सके।

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में समानता सुनिश्चित करना

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के तहत कवर किए गए समाज के हाशिए के वर्गो के लिए योजना के लाभों का विस्तार करने हेतु नए सिरे से प्रोत्साहन दिया गया है। इसी तरह, एबीपीएम-जय ने लिंग-विशिष्ट समानता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया है। पूर्ववर्ती आरएसबीवाई योजना में परिवार के सदस्यों के ऊपरी सीमा पर कैप था, जिसके कारण घर के औरतों का उपचार नहीं हो पाता था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एबी पीएम-जय परिवार के सदस्यों की संख्या को कैप नहीं किया गया है। जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। एनएचए आईटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बनाए गए आयुष्मान कार्डो में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 50% और अधिकृत अस्पताल में भर्ती होने वालों में 47% है।

मजबूत, विस्तृत और अंतर-संचालित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म

पहले की योजनाओं को लागू करने में यह देखने को मिला था कि आइटी सिस्टम की एकरूपता नहीं होने के कारण वितरण प्रभावित होता था। इस समस्या को दूर करने के लिए एबी पीएम-जय के तहत, लाभार्थी की पहचान, लेन-देन प्रबंधन और अस्पताल के पैनल में सहायता के लिए एक अत्यधिक बहुमुखी प्रौद्योगिकी मंच को विकसित किया गया है। अपनी नवीनता एवं परिवर्तनात्मकता के कारण सम्मानित हो चुकी यह आईटी प्लेटफॉर्म अब 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय है। इससे एनएच-एसएचए स्तर पर साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और जरूरी सुधार में सहायता मिलती रही है।

सार्वजनिक और निजी भागीदारी

आयुष्मान भारत पीएम -जय के तहत योजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी ने योजना के लाभार्थियों के लिए इलाज की तलाश करने के रास्ते बढ़ा दिए हैं और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में तृतीयक देखभाल सुविधाओं पर बोझ कम कर दिया है। एबी पीएम-जय के तहत, यह सुनिश्चित किया गया था कि सार्वजनिक अस्पतालों को उनकी सेवाओं के लिए समान रूप से और निजी अस्पतालों के समान दरों पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों को 'अनटाइड फंड' का एक पुल बनाने में भी मदद की है, जिसे बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों में स्थायी रूप से निवेश किया जा सकता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अस्पतालों की पूरक भूमिका यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रही है कि योजना का क्रियान्वयन निर्बाध रूप से आगे बढ़े।

आपके द्वार आयुष्मान

एनएचए का कार्यभार संभालने के बाद मैंने जिन प्रमुख गतिविधियों को हरी झंडी दिखाई, उनमें से एक है 'आपके द्वार आयुष्मान'। आपके द्वार आयुष्मान के तहत, फ्रंटलाइन हेल्थकेयर वर्कर्स, ग्राम पंचायत अधिकारियों और गांव-आधारित डिजिटल उद्यमियों के एक जमीनी नेटवर्क का उपयोग समुदायों में लाभार्थियों तक घर-घर पहुंचकर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए किया गया था। दिहाड़ी मजदूरों के लिए विशेष रात्रि शिविर लगाए गए। इन प्रयासों का का ही नतीजा है कि जनवरी 2021 से 4.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्डो के निर्माण हुआ, एनएचए आईटी सिस्टम द्वारा बनाए गए आयुष्मान कार्डो में 55% की वृद्धि हुई। एनएचए नए जोश के साथ आपके द्वार आयुष्मान कार्ड ड्राइव को पुन: लॉन्च करने जा रहा है। इस बार हम असम, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

अंत में, मैं एबी पीएम-जय को सफलता के सोपान पर पहुंचाने में अथक परिश्रम करने के लिए एनएचए, एसएचए, डीआईयू, क्रियान्वयन सहायता एजेंसियों, प्रधान मंत्री आरोग्य मित्र, फ्रंटलाइन हेल्थकेयर वर्कर्स, आयुष्मान कार्ड बनाने वाली एजेंसिया जैसे सीएससी / यूटीआईआईटीएसएल से मिलकर बने पूरे आयुष्मान भारत पीएम- जय इकोसिस्टम को भी इसका श्रेय देना चाहूंगा। हालांकि, इस योजना को अपनी पूरी क्षमता का दोहन करने में मदद करने के लिए आगे अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

राज्य सरकार ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है

शिमला। पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर बल दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने 412 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। इन पंचायतों के निर्माण के साथ, हिमाचल सरकार का लक्ष्य लोगों को सुविधा प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास सुनिश्चित करना है।

प्रदेश में 14वें वित्तायोग के तहत विभिन्न विकास कार्यो के लिए ग्राम पंचायतों को 850.17 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई, जिसमें से लगभग 700 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। 15वें वित्तायोग के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 के लिए पंचायतों के विकास के लिए 429 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 317 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के तहत गत चार वर्षो के दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों को 633. 18 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं और वर्ष 2021-22 के लिए 248. 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के अन्तर्गत जिला सिरमौर में 5.65 करोड़ रुपये, जिला किन्नौर में 3.65 करोड़ रुपये तथा जिला ऊना में 5.50 करोड़ रुपये की लागत से जिला संसाधन केंद्र बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के पंचायत भवनों के स्तरोन्नयन व मुरम्मत के लिए 700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 69 पंचायत भवनों पर 5.71 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। पंचायत घरों में लोक सेवा केंद्रों के निर्माण के लिए 27.44 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें से लगभग 16.45 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 5.38 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें से 2.44 करोड़ रुपये व्यय कर 5124 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 की योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 164.43 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं, जिसके अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने, जिला पंचायत संसाधन केंद्र तथा 1924 कॉमन सर्विस केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में सामुदायिक केंद्रों के निर्माण, स्तरोन्नयन के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में 252 ग्राम पंचायातों को 17.06 करोड़ रुपये, 2020-21 में 22.79 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2021-22 में 148 ग्राम पंचायतों को 22.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के डिजिटीकरण के तहत 412 नई ग्राम पंचायतों को ई-पंचायतों से जोड़ने के लिए दो करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्ट्रर ऑनलाइन कर 1 अप्रैल, 2018 से लोगों को परिवार रजिस्ट्रर की ऑनलाइन प्रतियां जारी की जा रही हैं। विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में योजना बनाने व लेख संधारण आदि का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक चम्बा चौगान में राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने चम्बा जिला के ऐतिहासिक चम्बा चौगान में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने तिरंगा फहराया और पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और एनएसएस की टुकड़ियों से सलामी ली।

परेड का नेतृत्व एसडीपीओ सलूणी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के मयंक चौधरी ने किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्रे नरेंद्र मोदी के संदेश का भी प्रसारण किया

गया। संदेश में प्रधानमंत्री ने भौगोलिक और अन्य बाधाओं के बावजूद राज्य की विकास यात्रा की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में राज्य ने ऊर्जा, बागवानी, पर्यटन और सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रगति की है।

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि डबल ईजन सरकारों के समन्वय से राज्य में सड़क नेटवर्क सुदृढ़ हुआ है तथा प्रदेश पर्यटन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में विकास के नए अवसर सृजित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य में सभी केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जय राम ठाकुर के ईमानदार नेतृत्व और परिश्रमी प्रदेशवासियों के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में उभरेगा।

मुख्यमंत्री ने इस पावन अवसर पर राज्य के लोगों का अभिनंदन करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों, हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के योगदान की सराहना की और जिन्होंने हिमाचल को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाया। उन्होंने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य को औद्योगिक पैकेज प्रदान किया था। उन्होंने कहा कि अटल टनल रोहतांग भी अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया। उन्होंने कहा कि 3500 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस सुरंग से लाहौल घाटी को हर मौसम में सड़क सम्पर्क प्रदान करने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक दिन पर राज्य के लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेश के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह पहला अवसर है जब किसी प्रधानमंत्री ने हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे महिलाओं को लगभग 60 करोड़ रुपये के लाभ प्राप्त होंगे। उन्होंने प्रथम जुलाई से सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक जीरो बिल की सुविधा प्रदान करने व उनसे कोई विद्युत बिल न लेने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के 11.5 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को 250 करोड़ रुपये के लाभ प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे सभी परिवारों से पानी का कोई बिल न लेने की भी घोषणा की, जिससे प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को 30 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान होंगे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर होली-उतराला सड़क के कार्य में तेजी लाने के लिए पांच करोड़ रुपये और चम्बा मुख्यालय में लोगों की सुविधा के लिए मिनी सचिवालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने चम्बा शहर के सौंदर्यीकरण तथा शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी घोषणा की।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य को भी कोरोना महामारी के कारण कठिन समय का सामना करना पड़ा है, लेकिन लोगों के सहयोग से प्रदेश न केवल इस स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम रहा बल्कि विकास की गति को भी निर्बाध रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को विकास के मामले में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष लगाव के कारण उनके कार्यकाल में राज्य को हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाएं की सौगात मिली हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और प्रदेश का तीव्र और संतुलित विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक में बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दिया, जिसे अब और घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 436 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे थे, जबकि वर्तमान में इस पर 1300 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों की शिकायतों का उनके घर-द्वार पर समाधान करने के उद्देश्य से जनमंच आयोजित करने की अनूठी पहल की है। अब तक 244 स्थानों पर आयोजित 25 जनमंच में प्राप्त 54,565 शिकायतों में से 90 प्रतिशत से अधिक का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज करवाकर निर्धारित समयावधि के भीतर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकता है। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन पर अब तक करीब 3.55 लाख शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 3.41 लाख का निपटारा किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है और उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर पारंपरिक चूल्हों और ईंधन लकड़ी इकट्ठा करने से काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के उन पात्र परिवारों के लिए मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की जो उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 3.25 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन सहित तीन सिलेंडर प्रदान किए जा रहे हैं, साथ ही 1.37 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष से इन दोनों योजनाओं के तहत लाभार्थियों को एक और अतिरिक्त मुफ्त सिलेंडर देने का निर्णय किया है और प्रदेश धुआंमुक्त राज्य घोषित होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने जनवरी, 2019 से हिमकेयर योजना आरम्भ की है, जिसके तहत लाभार्थी परिवार के पांच सदस्यों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक की निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 5.40 लाख परिवारों को हिमकेयर योजना के तहत पंजीकृत किया गया है और 218 करोड़ रुपये व्यय कर 2.40 लाख मरीजों को कैशलेस ईलाज उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रतिमाह प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 18 हजार लाभार्थियों को 60.50 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 31 हजार रुपये की वित्तीय सहायता गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत स्टार्टअप के लिए एक करोड़ रुपये तक की मशीनरी, उपकरण और औद्योगिक संयंत्र में निवेश करने पर युवाओं को 25 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत उपदान को अब महिलाओं के लिए 30 से बढ़ाकर 35 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजनों के लिए 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत उपदान कर दिया गया है। अब तक, लगभग 624 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 3758 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं जिससे 10 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र को एक नया आयाम देने में 'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना' कारगर साबित हुई है और 1.68 लाख से अधिक प्रगतिशील किसानों ने इस योजना को अपनाया है। उन्होंने कहा कि नवम्बर, 2019 को प्रदेश के धर्मशाला में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें 96,721 करोड़ रुपये के निवेश के 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि 13,656 करोड़ रुपये की लागत के 240 परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग शिमला में आयोजित की गई और 27 दिसंबर, 2021 को राज्य सरकार के चार साल के कार्यकाल के पूर्ण होने के अवसर पर मंडी में प्रधानमंत्री द्वारा 28,197 करोड़ रुपये के 287 परियोजनाओं की दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई राहें-नई मंजिलें योजना के तहत 200 करोड़ रुपये से राज्य में विभिन्न पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अकुशल दैनिक वेतन भोगियों के न्यूनतम वेतन में 50 रुपये की बढ़ोतरी के साथ न्यूनतम वेतन 350 रुपये प्रति दिन और वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान दैनिक वेतन में 140 रुपये की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1700 रुपये, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को 1825 रुपये बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि एस.एम.सी. शिक्षकों के मानदेय को 1000 रुपये बढ़ाया गया है। इसी प्रकार विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में भी 900 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन पुस्तकालय सुविधा आरम्भ करने के लिए जिला प्रशासन कुल्लू (उपायुक्त आशुतोष गर्ग), टीकाकरण अभियान में अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एम.डी. एन.एच.एम. हेमराज बैरवा) और टीकाकरण अभियान में उपलब्धि के लिए जिला प्रशासन किन्नौर (उपायुक्त आबिद हुसैन) को सिविल सेवा पुरस्कार प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने पुलिस ऑर्केस्ट्रा हार्मनी ऑफ द पाइन्स, बेसहारा पशुओं की सहायता के लिए एन.जी.ओ. क्रांति के धीरज महाजन, भारत के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी, डॉ. टेक चंद, पद्मश्री बाबा इकबाल सिंह (प्राप्तकर्ता सरदार जगजीत सिंह), पद्मश्री विद्यानंद सरैक, पद्मश्री ललिता वकील, प्रसिद्ध लेखक डॉ. गौतम शर्मा, डॉ. प्रीत्यूष गुलेरी और विजय राज उपाध्याय को प्रेरणा स्रोत पुरस्कार-2022 प्रदान किए गए।

उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (मुकेश रेशपर ने पुरस्कार प्राप्त किया) और डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की डॉ. निवेदिता शर्मा को राज्य नवाचार पुरस्कार-2022 भी प्रदान किया।

इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

राज्य विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, सांसद किशन कपूर, मुख्य सचेतक विक्रम जरयाल, विधायक पवन नैय्यर और जिया लाल कपूर, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा, उपायुक्त चम्बा डी.सी राणा, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल

की 157वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए निगम के व्यवसाय को आगे बढ़ाने तथा सभी इकाइयों को लाभप्रद बनाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।

उन्होंने इस दिशा में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने प्रभावी विपणन के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने चिन्हित इकाइयों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए निगम के प्रयासों पर प्रसनन्ता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने कुल्लू-मनाली-केलांग-जिस्पा सर्किट में पर्यटन को और बढ़ाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऑक्युपेंसी विश्लेषण, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, होटलों व सेवाओं के प्रचार प्रसार के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा।

बैठक में बोर्ड ने 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले दैनिक भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की अनुमति प्रदान की। बोर्ड ने सभी पात्र आवेदकों को करुणामूलक आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का अनुमोदन किया। बोर्ड ने विभिन्न श्रेणियों के 107 प्रशिक्षुओं को नियमों के अनुसार निगम में समायोजित करने का निर्णय लिया। बैठक में वित्त वर्ष 2022 -23 का बजट भी अनुमोदित किया गया।

निगम के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने निगम के व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभासीष पंडा, प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार और विशेष सचिव रोहित जमवाल उपस्थित थे।

प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में आयोजित होंगी रेडक्रॉस की गतिविधियां: राज्यपाल

माता एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल विषय पर सप्ताह भर चलेंगे कार्यक्रम

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो राज्य रेडक्रॉस के अध्यक्ष भी हैं, ने रेडक्रॉस के स्वयं सेवकों का आह्वान किया कि उन्हें संगठन के माध्यम से समाज को अपना बहुमूल्य योगदान देने के भाव से आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे रेडक्रॉस से जुड़कर परिवार के रूप में कार्य करें जिससे समाज सेवा के बेहतर परिणाम सामने आएंगे। राज्यपाल रेडक्रॉस भवन में हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हर वर्ष 8 मई को अंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर रेडक्रॉस का झण्डा पिनअप कर संगठन की गतिविधियों को और प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए धनराशि एकत्रित की जाती है। उन्होंने कहा कि 8 मई के बाद भी पूरे सप्ताह विभिन्न गतिविधियां संचालित की जानी चाहिएं। उन्होंने कहा कि इस बार रेडक्रॉस माता एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के अपने विषय को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करेगा। जिला स्तर पर उपायुक्तों और जिला रेडक्रॉस सचिवों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अस्पतालों को इस कार्य में जोड़कर ज़मीनी स्तर पर कार्य किया जाएगा।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि अस्पताल कल्याण शाखा की सभी सदस्य केवल अस्पतालों तक ही सीमित न रहकर क्षेत्रीय स्तर पर भी अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि समस्याओं से भागने की ज़रूरत नहीं है, उनके समाधान के लिये मिलकर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस ईश्वरीय कार्य है, जो हमारे माध्यम से हो रहा है। रेडक्रॉस एक बड़ा संगठन है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है। हमें इससे जुड़कर प्रदेश स्तर पर बेहतर करके दिखाना है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में रेडक्रॉस ब्लड बैंक शीघ्र बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने इस मौके पर रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय रेडक्रॉस प्रबंधन समिति की सदस्य डॉ. साधना ठाकुर ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत करते हुए गत दो वर्षों की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा ने कोरोना महामारी के दौरान व्हाट्स एप्प ग्रुप बनाकर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाई। उन्होंने कहा कि 22 चिकित्सकों का पैनल तैयार किया गया था, जो अपने स्लॉट पर कोरोना मरीज़ों से बात करते थे। इस दौरान राष्ट्रीय इकाई से काफी मदद मिली। उन्होंने कहा कि वन विभाग के सहयोग से रेडक्रॉस ने वन महोत्सव का आयोजन कर एक दिन में एक लाख पौधे रोपित किये। इस दौरान, रक्तदान शिविर, आश्रमों का दौरा, स्वास्थ्य किट का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवकों ने मास्क तैयार कर उनका वितरण, कम्बल, टेंट, निःशुल्क राशन इत्यादि गरीबों को रेडक्रॉस के माध्यम से दिए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मई के अंतिम सप्ताह तथा जून के पहले सप्ताह के बीच रेडक्रॉस मेले का आयोजन किया जाएगा।

इससे पूर्व, राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अवैतनिक सचिव डॉ. किमी सूद ने राज्यपाल का स्वागत किया।

राज्य रेडक्रॉस के सचिव संजीव कुमार ने राज्यपाल तथा अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया।

राज्यपाल के सचिव एवं राज्य रेडक्रॉस के महासचिव विवेक भाटिया ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की उपाध्यक्ष मधु सूद ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

अस्पताल सेवा के चार साल, उपलब्धियाँ बेमिसाल:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल । केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रयास संस्था द्वारा चलाई जा रही सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा 'अस्पताल' के चार वर्षो के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा बताते हुए इस अवसर पर ऊना में आयोजित विशाल चिकित्सा शिविर के सफल आयोजन पर अस्पताल टीम को बधाई दी।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा 'संविधान निर्माता बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर गरीब कल्याण के बड़े हिमायती थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने 14 अप्रैल 2018 को प्रयास स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की थी। बेहतर स्वास्थ सुविधा प्रत्येक नागरिक की बुनियादी ज़रूरत है, मगर कई बार स्वास्थ केंद्रों के दूर होने या डॉक्टरों की उपलब्धता न होने से दूर दराज़ इलाक़ों के लोग अच्छी स्वास्थ सेवा से वंचित रह जाते हैं, ऐसे में अस्पताल सेवा लोगों के लिए एक वरदान बनी है। सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा ने 4 वर्षो में लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम किया है। मात्र चार वर्ष में 6,22,354 किलोमीटर का चक्कर काटकर क़रीब 7,151,32 लोगों को उनके घर द्वार पर मुफ्त जाँच, सलाह और उपचार करना अपने आप में एक उपलब्धि है जिसके लिए उन्होने अस्पताल टीम को बधाई दी।

अनुराग ठाकुर ने कहा '2018 में 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट से शुरू हुए अस्पताल के बेड़े में अब 32 गाड़ियाँ जुड़ चुकी हैं। आज 7 जिले, 23 विधानसभा क्षेत्र, 1350 से ज्यादा पंचायतें और 6400 से ज्यादा गाँव इस अनूठी सेवा से लाभान्वित हो रहे हैं। आधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से परिपूर्ण सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की वैनों में डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्निशन और ड्राइवर तैनात होते हैं। वैन में डायग्नोस्टिक सेंटर और पैथोलॉजी लैब भी है। इसमें लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी, केएफटी, शुगर ग्लूकोस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसे अलग-अलग 40 टेस्ट की सुविधा और उनकी दवाएं भी मौजूद रहती हैं। अस्पताल सेवा की चौथी वर्षगाँठ पर 4 और विधानसभा नाहन, पावंटा साहिब, देहरा व जसवां प्रागपुर के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखा कर रवाना करने के लिए माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी का आभार प्रकट किया।

अनुराग ठाकुर ने कहा महामारी के समय भी अस्पताल सेवा के पहिए थमे नहीं बल्कि चाहे बिलासपुर में डेंगू फैलना हो या कोरोना महामारी के दौरान अस्पताल सेवा का राज्य सरकार के साथ मिलकर कोविड प्रसार को रोकना हो और दवा वितरण व इसकी प्राथमिक जाँच में अपना सहयोग देने का काम हो। अस्पताल सेवा के 65 फीसदी लाभार्थी महिलाएं और बुजुर्ग हैं। मोबाइल यूनिट पर जो कर्मचारी तैनात किए गये हैं उनमें 50 फीसदी स्वास्थ्य कर्मचारी महिलाएँ हैं जोकि महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है। इस चलते फिरते अस्पताल में सामान्य बुख़ार के ईलाज से लेकर स्तन कैंसर तक की जांच हो रही है और समय-समय पर चिकित्सा शिविरों के माध्यम देश के बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने का काम किया जाता है। 7 लाख लाभार्थियों के इस सफ़र को अभी बहुत दूर तक जाना है। अस्पताल सेवा यूँ ही बिना रुके, बिना थके चलती रहेगी और सेवा करती रहेगी।

चम्बा में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन के लिए हिमाचल प्रदेश और एनएचपीसी के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की उपस्थिति में चम्बा में मोबिलिटी क्षेत्र के लिए पायलट हाइड्रोजन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन चम्बा और एनएचपीसी लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

एनएचपीसी के समूह महाप्रबंधक ए.के. पाठक ने एनएचपीसी तथा चम्बा के उपायुक्त ने राज्य सरकार की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा और 2030 तक भारत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट उत्पन्न करेगा, जो कुल स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत होगा। एनएचपीसी के सहयोग से राज्य सरकार की यह पहल एक मील का पत्थर साबित होगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हस्ताक्षरित किए गए समझौता ज्ञापन से इस पायलट हाइड्रोजन परियोजना के निष्पादन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में 300 किलोवाट का ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी प्लांट स्थापित किया जाएगा और इससे उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रोलाइजर में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 20 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न होगा और इसे अनुकूल प्रक्रिया के माध्यम से संग्रहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक किलोग्राम हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन के लिए 9 से 12 लीटर पानी का उपयोग होगा।

एनएचपीसी के समूह महाप्रबंधक एस.के. संधू ने कहा कि यह परियोजना एनएचपीसी के अध्यक्ष ए.के. सिंह की पहल है, जिसके अन्तर्गत उत्पादित हाइड्रोजन को 20 किलोग्राम क्षमता वाली बस/कार आदि के ईंधन टैंक में संग्रहित किया जाएगा और यह हाइड्रोजन मुख्य ईंजन में लगे हाइड्रोजन ईंधन सैल में जाएगा। इस ऊर्जा का उपयोग चम्बा के स्थानीय क्षेत्र में इस 20 किलोग्राम ईंधन टैंक के साथ लगातार 8 घंटे या 200 किलोमीटर तक बस चलाने के लिए किया जाएगा। एनएचपीसी इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक 32+1 सीटर बस भी उपलब्ध करवाएगी, जो कार्बन का शून्य उत्सर्जन करेगी और क्षेत्र की परिवहन सुविधाओं में सुधार करेगी।

बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने वित्त वर्ष 2022-23 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं के समयबद्ध कार्यन्वयन के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि लोगों को सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को तत्परता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किसी भी तरह की कोताही न की जाए तथा किसी भी विकासात्मक कार्य में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के साथ-साथ विभिन्न फील्ड अनाउंसमेंट के लंबित मामलों को भी तत्परता से पूरा किया जाए। विभाग किसी भी कार्यक्रम या योजना को लागू करने से पूर्व उसका प्रभावी व रचनात्मक प्रस्ताव तैयार करें। अभिनव योजनाओं के प्रभावी परिणाम सामने आने चाहिए ताकि लक्षित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए प्रयासों व पहल के सकारात्मक परिणाम आने पर अधिकारियों की ऊर्जा व प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। यह अन्य व्यक्तियों के लिए भी प्रेरणा बनती है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की परिधि का संख्या एवं परिव्यय की दृष्टि से प्रभावी विस्तार किया गया है। इस योजना के लाभार्थियों को इसका समयबद्ध लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए बजट में किए गए प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के निर्देश भी दिए।

जय राम ठाकुर ने कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक कृषि पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पाठयक्रम में संशोधन की प्रक्रिया में और तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इसे आगामी शैक्षिक सत्र से लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण, जल शक्ति, पर्यटन, पशुपालन, ग्रामीण व शहरी विकास, शिक्षा, उद्योग व अन्य सभी विभागों के कार्यक्रमों से जुड़ी घोषणाओं के प्रावधानों को तय समय में कार्यान्वित करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या जयराम के वकील नड्डा और अनुराग ठाकुर जवाब देंगे

- सरकार दोहरे मापदंड क्यों अपना रही?
- मुख्य सचिव के खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज हो सकता
- पी चिदंबरम के साथ अभियुक्त बने प्रबोध सक्सेना को लेकर सरकार की क्या मजबूरी है
- शैल की आवाज दबाने के लिये किस हद तक जायेगी सरकार

2017 में प्रबोध सक्सेना द्वारा स्वयं जारी पत्र का अब उन्ही पर अमल क्यों नही

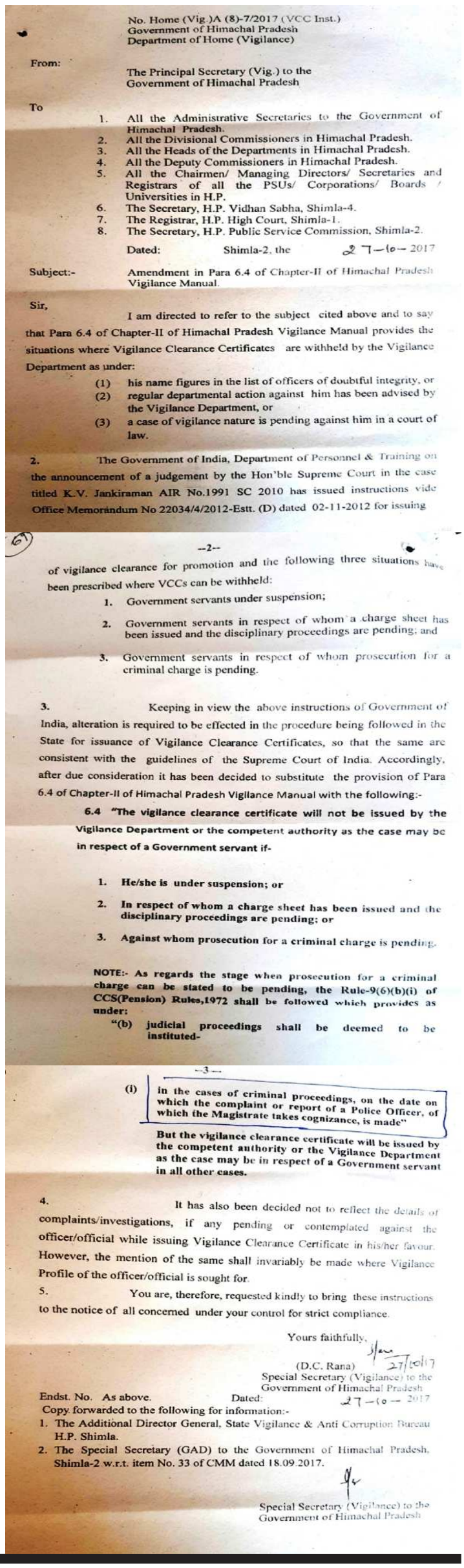

No. Home (Vig.)A (8)-7/2017 (VCC Inst.)
Government of Himachal Pradesh
Department of Home (Vigilance)

From: The Principal Secretary (Vig.) to the Government of Himachal Pradesh

To
1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
3. All the Heads of the Departments in Himachal Pradesh.
4. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
5. All the Chairmen/ Managing Directors/ Secretaries and Registrars of all the PSUs/ Corporations/ Boards / Universities in H.P.
6. The Secretary, H.P. Vidhan Sabha, Shimla-4.
7. The Registrar, H.P. High Court, Shimla-1.
8. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2.

Dated: Shimla-2, the 27-10-2017

Subject:- Amendment in Para 6.4 of Chapter-II of Himachal Pradesh Vigilance Manual.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that Para 6.4 of Chapter-II of Himachal Pradesh Vigilance Manual provides the situations where Vigilance Clearance Certificates are withheld by the Vigilance Department as under:

(1) his name figures in the list of officers of doubtful integrity, or
(2) regular departmental action against him has been advised by the Vigilance Department, or
(3) a case of vigilance nature is pending against him in a court of law.

2. The Government of India, Department of Personnel & Training on the announcement of a judgement by the Hon'ble Supreme Court in the case titled K.V. Jankiraman AIR No.1991 SC 2010 has issued instructions vide Office Memorandum No 22034/4/2012-Estt. (D) dated 02-11-2012 for issuing

--2--

of vigilance clearance for promotion and the following three situations have been prescribed where VCCs can be withheld:

1. Government servants under suspension;
2. Government servants in respect of whom a charge sheet has been issued and the disciplinary proceedings are pending; and
3. Government servants in respect of whom prosecution for a criminal charge is pending.

3. Keeping in view the above instructions of Government of India, alteration is required to be effected in the procedure being followed in the State for issuance of Vigilance Clearance Certificates, so that the same are consistent with the guidelines of the Supreme Court of India. Accordingly, after due consideration it has been decided to substitute the provision of Para 6.4 of Chapter-II of Himachal Pradesh Vigilance Manual with the following:-

6.4 "The vigilance clearance certificate will not be issued by the Vigilance Department or the competent authority as the case may be in respect of a Government servant if-

1. **He/she is under suspension; or**
2. **In respect of whom a charge sheet has been issued and the disciplinary proceedings are pending; or**
3. **Against whom prosecution for a criminal charge is pending.**

NOTE:- As regards the stage when prosecution for a criminal charge can be stated to be pending, the Rule-9(6)(b)(i) of CCS(Pension) Rules,1972 shall be followed which provides as under:

"(b) judicial proceedings shall be deemed to be instituted-

--3--

(i) **in the cases of criminal proceedings, on the date on which the complaint or report of a Police Officer, of which the Magistrate takes cognizance, is made"**

But the vigilance clearance certificate will be issued by the competent authority or the Vigilance Department as the case may be in respect of a Government servant in all other cases.

4. It has also been decided not to reflect the details of complaints/investigations, if any pending or contemplated against the officer/official while issuing Vigilance Clearance Certificate in his/her favour. However, the mention of the same shall invariably be made where Vigilance Profile of the officer/official is sought for.

5. You are, therefore, requested kindly to bring these instructions to the notice of all concerned under your control for strict compliance.

Yours faithfully,

(D.C. Rana) 27/10/17
Special Secretary (Vigilance) to the Government of Himachal Pradesh

Endst. No. As above. Dated: 27-10-2017

Copy forwarded to the following for information:-
1. The Additional Director General, State Vigilance & Anti Corruption Bureau H.P. Shimla.
2. The Special Secretary (GAD) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 w.r.t. item No. 33 of CMM dated 18.09.2017.

Special Secretary (Vigilance) to the Government of Himachal Pradesh

क्या 'जय और तय'

...पृष्ठ 1 का शेष

शिमला/शैल। पिछले दिनो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जब अपने ही गृह राज्य हिमाचल के दौरे पर आये थे तब उन्होंने प्रदेश में चल रही नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर विराम लगाते हुये यह भी कहा था कि वह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के वकील हैं। इसी के साथ धूमल की उस मांग पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। जिसमें धामी की तर्ज पर उनकी हार के कारणो की जांच करने का आग्रह किया गया था। धूमल प्रकरण को भी यह कहकर विराम लगा दिया कि भाजपा गुण दोष के आधार पर फैसला लेती है। नड्डा के इस ब्यान के राजनीतिक अर्थ चाहे जो भी निकाले जायें लेकिन इससे यह आवश्य स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले दिनों में जयराम और उनकी सरकार पर उठने वाले सवालों का जवाब नड्डा तथा अनुराग ठाकुर से भी पूछा जा सकता है। क्योंकि उन्होंने सरकार के वकील होने का दावा किया है। इसी दावे पर अमल करते हुये अनुराग ठाकुर ने आप के पांव प्रदेश में लंबे होने से पहले ही उस में तोड़फोड़ करके आप को प्रदेश इकाई भंग करने के मुकाम तक पहुंचा दिया। आने वाले दिनों में भाजपा और आप में क्या-क्या घटता है यह देखना दिलचस्प होगा।

लेकिन आगामी राजनीतिक घटनाक्रम के आकार लेने से पहले ही प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय से जांच किये जाने की संस्तुतिक जो पत्र पिछले करीब छः माह से मुख्यमंत्री सचिवालय की अपनी ही फाइलों के नीचे दबा पड़ा था अचानक बाहर आकर एक बड़े समाचार की शक्ल ले गया। जिस पर मुख्यमंत्री को भी स्वयं प्रतिक्रिया देनी पड़ी। लेकिन मुख्यमंत्री यह प्रक्रिया देते हुए भूल गये कि इससे वह स्वयं ही दोहरे मापदंडों के आरोप में आ खड़े होते हैं। क्योंकि 2020 में ऐसा ही एक पत्र पीएमओ से शैल कार्यालय को लेकर आया था। इस पत्र पर बाकायदा विजिलैंस में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के शिकायतकर्ता और उसकी शिकायत तथा उसके ब्यान की कॉपी विजिलैंस से मांगी गयी जो आज तक नहीं मिली है। जिसका अर्थ है कि शिकायत छद्म नाम से की गयी और प्रदेश सरकार के ही गृह एवं सतर्कता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार ऐसी शिकायतों पर जांच नहीं की जा सकती। लेकिन जयराम सरकार ने शैल की आवाज को दबाने के लिये यह सब किया। परंतु आज मुख्य सचिव के खिलाफ शिकायतें आने पर कोई मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। अब यह दोहरे मापदंड क्यों अपनाये जा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री के वकील नड्डा और अनुराग इन दोहरे मापदंडों का कारण बतायेंगे।

यही नहीं सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना पी चिदंबरम मामले में सह अभियुक्त हैं। सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया हुआ है। इस मामले के चलते उन्हें ओ डी आई सूची में होना चाहिये और नियमानुसार इस मामले के लंबित रहते उन्हें पदोन्नत नहीं किया जा सकता। हिमाचल सरकार ने भी अपने 27-10-2017 के पत्र में इस आशय के स्पष्ट निर्देश जारी किये हुये हैं। लेकिन जयराम सरकार ने इन निर्देशों को भी अंगूठा दिखाते हुये प्रबोध सक्सेना को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी देने के साथ ही पदोन्नति भी दी है। प्रबोध सक्सेना एक योग्य अधिकारी हो सकते हैं लेकिन क्या सरकार ने ऐसे निर्देश उन लोगों को दंडित करने के लिये बना रखे हैं जो गुण दोष के आधार पर सरकार की हां में हां मिलाते हैं। क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ ऐसे कोई मामले होते हैं वह सरकार को खुश करने के लिये कोई भी अवांछित फैसला लेने के लिये तैयार रहते हैं। इसमें यह भी सवाल उठता है कि राजनीतिक नेतृत्व ऐसे लोगों पर अपनी विश्वसनीयता कैसे बना लेता है। क्या ऐसे राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व के हाथों में कोई भी देश प्रदेश ज्यादा देर तक सुरक्षित रह सकता है? जयराम सरकार के कार्यकाल में ऐसे दर्जनों मामले घटे हैं जहां अदालतों के फैसलों पर भी अमल नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में ऐसे मामले पाठकों के सामने पूरे विस्तार के साथ रखे जायेंगे ताकि जनता एक स्वस्थ फैसला ले सके।

सही है कि सुक्खू छः वर्ष तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन उनकी अध्यक्षता में कितनी चुनावी सफलताएं मिली है यह एक अलग विषय बन जाता है। इस समय सदन में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मुकेश अग्निहोत्री निभा रहे हैं। जयराम के कार्यकाल में कारगर विपक्ष की भूमिका कांग्रेस की जितनी सदन में सफल रही है उतनी सदन से बाहर नहीं रही है। पालमपुर के नगर निगम और फिर मंडी के लोकसभा उपचुनाव का संचालन मुकेश के पास रहा है। ऐसे में यदि मुकेश के समर्थक भी ऊना में ऐसे ही नारे लगाने पर आ जाये तो क्या संदेश जायेगा। आशा कुमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हैं क्या मुख्यमंत्री बनने के लिये उनकी योग्यताएं कम हो जाती हैं। इसी तरह आनंद शर्मा, कौल सिंह ठाकुर, रामलाल, सुरेश चंदेल और हर्षवर्धन चौहान तक कांग्रेस में नेताओं की लंबी सूची है। हॉलीलॉज अभी काफी वक्त तक सत्ता का केंद्र रहेगा क्योंकि हर चुनाव में स्व. वीरभद्र सिंह का नाम लिया ही जायेगा। इस वस्तु स्थिति में यदि कांग्रेस के नेता अपने-अपने नारे लगवाने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं तो उसे न केवल उनका अपना और संगठन का ही अहित होगा बल्कि प्रदेश की जनता के साथ भी धोखा होगा। क्योंकि जिस सरकार ने आकंठ कर्ज के बोझ तले प्रदेश में सत्ता में बने रहने के लिये मुफ्ती की मीठी गोली देकर और कर्ज बढ़ाने का दाव चल दिया हो उसे हल्के में लेना सही नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस को पहले सदन में सरकार बनाने लायक बहुमत जुटाने को प्राथमिकता देनी होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए एक दूसरे का गला काटने की योजनाओं को अंजाम देना होगा। क्योंकि विपक्ष में आप कांग्रेस से पहले अपनी गिनती करवाने में सफल हो गयी है। जबकि कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में आप को भाजपा की बी टीम होने का फतवा देकर चुप बैठ गयी है। इस फतवे को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य लेकर जनता की अदालत में नहीं आयी है। यदि कांग्रेस इस मनोविकार से समय रहते बाहर नहीं निकलती है तो उसके लिये लंबे तक ''दिल्ली दूरस्थ'' हो जायेगी।